RAJYA SABHA

Wednesday, the 24th July, 1996/2nd Shravana, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Providing Public Telephones in villages

*201. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:†
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the six lakh villages are to be connected with Village Public Telephone (VPTS) by 1997 as stipulated in the new Telecom Policy; and

(b) if so, the details of the progress made so far in meeting the target since its launching?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी हां,

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में यह परिकल्पना की गई है कि देश के सभी गांवों में 1997 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जानी चाहिए।

(ख) पिछले दो वर्षों (1994-96) में 79155 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 1.4.1996 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से युक्त ग्रामों की संख्या 216632 है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, it is all well known that the telecommunication systems, particularly the system meant for poor people—post—cards and telegrams—are in a serious disarray. Or, I should submit that the normal postal telecommunication is in a serious crisis. Post-cards do not reach the people even within a month. Normal telegrams also are delivered excessively late. Therefore, the only communication channel left in this country which is in a better working condition is the telephones. The Government has promised that by 1977, all the six lakh villages will be covered with the telecommunication systems. Now, as the hon. Minister admits, till date, the Government has been able to provide telephones only to less than half that number of villages, that is, 2,16,632. That means a majority of the villages have not been covered. Last year, they had provided only less than one lakh of telephones.

Therefore, part (a) of my supplementary is this. If the Government could achieve the target by 1997, why has it not reached the possible figure by now? What is the reason for this failure, culpable failure? Was it because of the financial crunch or was not the Government serious? And, part (b) of my supplementary is, is the Government aware that in the places where there are telephone connections, particularly in rural areas, most of the telephones are not in working condition? Therefore, what steps will the Government take to make the system a little more responsive?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमान, गुप्ता जी को हम धन्यवाद देंगे जो उन्होंने यह प्रश्न करके हमारी भी जानकारी बढ़ाने का काम किया। श्रीमान, यह सही है कि गांवों में संचार व्यवस्था जो आज के वातावरण में होनी चाहिए, वह नहीं है। विकास का लाभ गांवों को जितना भी मिले हमको विकास की दृष्टि से संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। यह भी सही है कि परिकल्पना यह की गई है कि नयी दूर संचार नीति में, 1997 में सभी ग्रामों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ दिया जाएगा।

पहले यह लक्ष्य था सिर्फ ग्राम पंचायतों को इस सुविधा से जोड़ा जाएगा लेकिन 1994 में इसमें परिवर्तन किया गया उसमें सभी गावों को ले लिया गया। लेकिन प्रगति से हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं। पिछले वर्ष का जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा नहीं हो पाया। हमने इस पर काफी गम्भीरता से विचार किया है और आप लोगों के जो सुझाव होंगे उन पर यथासमय अमल करने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष कुछ परिवर्तन किये हैं...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: कारण क्या है?

Why could theyy not do it?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: हमने इस साल 75 हजार ग्रामीण टेलीफोन का लक्ष्य रखा है और उसके लिए 600 करोड़ का बजटरी प्रोविज़न अलग से कर दिया है। इस 600 करोड़ रुपये को किसी दूसरी मद में खर्च नहीं किया जाएगा। पिछले वर्षों में इक्विपमेंट सप्लाई में थोड़ी देरी हुई, उसी के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। श्रीमन, यह भी सही है कि गांवों में जो टेलीफोन लगे हैं, वह ठीक से काम भी

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta.

नहीं कर रहे है खास तौर से एम.ए.आर.आर., इसको हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे: कारण क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: पहले डिज़ाइन का था, कुछ इक्विपमेंट के कारण था। उसमें सुधार किया जा रहा है। (व्यवधान) सुन लीजिये फिर आप जो पूछेंगे हम जवाब देंगे। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: हमने अभी विभाग को आदेश दिये हैं कि जितने ग्रामीण टेलीफोन हैं, उनकी रोज़ाना जांच की जाए कि ठीक है या नहीं है। हफ्ते में सी.जी.एम. को रिपोर्ट भेजी जाए और एक महीने में हमारे दिल्ली दफ्तर में रिपोर्ट भेजी जाए। यह भी हम कोशिश करेंगे कि तीन महीने में यदि सुधार में प्रगति नहीं होगी तो वहां के अधिकारियों को थोड़ा कड़ा निर्देश देंगे।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I am thankful to the Minister because he has spoken very frankly. But that does not hold out any promise of a change in the situation. Anyway, as per the policy of the Government, it was suggested that 10 per cent of the new connections which are required to be given by the private telephone companies, will have to be given in the rural areas. That was the commitment of the Government. Therefore, the completion of the target depends on the participation of the private sector. Now, the private sector which have been given the contract, as per my information, have not finally signed the contract. Only a letter of intent has been issued. I would like to know whether the private companies who have been given the letter of intent recently by the new Government have signed them. How long will it take for them to sing the same? What is the time-frame?

Secondly, if 10 per cent of the new connections are to be given in the rural areas by the private companies, then will the Government see to it that it is observed in letter and spirit? There is a talk going on that a number of private companies in whose favour the letters of intent have been issued are considering to withdraw because they found that the contract has not been as favourable as they considered it in the beginning.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, जो निजीकरण की नीति अपनाई गई है उसके अन्तर्गत बिडिंग हुई, लेटर आफ इंटेंट जारी हुआ। एग्रीमेंट लॉ डिपार्टमेंट से वेट हो कर हमारी गार्वनमेंट के पास आया, लेटर आफ इंटेंट पहले ही जारी हो गया था। अब पार्टीज़ को साइन करने के लिए 31 जुलाई तक समय दिया गया है और जो टेंडर कंडीशंस थीं उसी में कहा गया था कि 10 प्रतिशत उनको ग्रामीण टेलीफोन लगाने पड़ेंगे और अगर 10 प्रतिशत ग्रामीण टेलीफोन लगा देंगे, उनके द्वारा भी करीब 2 लाख गांवों को यह सुविधा प्राप्त हो जाएगी और यही नेशनल टेलीकाम पालिसी में परिकल्पना की गई थी।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Is there any penalty clause stating therein that if they do not do it, then a penalty will be imposed?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: हां, अगर वे नहीं करते हैं तो पेनाल्टी का प्रावधान उसमें पहले से दिया हुआ है।

श्री सूर्यभान पाटिल वाहादने: सभापति महोदय, केन्द्र की ओर से ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन सेवा के अंतर्गत जो स्कीम चल रही है उसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूं। मैं ग्राम में रहने वाला हूं और पूरे महाराष्ट्र में ग्राम में ही प्रवास करता हूं। कई ग्राम पंचायतों में जो इस स्कीम के अंतर्गत टेलीफोन दिए गए हैं वे बंद अवस्था में हैं। तो मेरा सवाल ऐसा है कि यह जो स्कीम चल रही है इसके बारे में बताएं कि ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है और क्या कारण है इसके बारे में कुछ सर्वे करने का क्या सरकार विचार करेगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य से हम कुछ हद तक सहमत हैं। हम भी गांव में ही रहने वाले हैं और हमारे घर पर भी यह लगा था और बहुत दिनों तक खराब ही रहता था...(व्यवधान) अब मंत्री हो गए है तो ठीक है। हम आपसे सहमत हैं। ग्राम टेलीफोनों की जो दशा है उस पर हम संतोष व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने आदेश दिए आते आते ही कि प्रतिदिन इन टेलीफोनों की जिस एक्सचेंज से संबंधित हैं, जांच करें कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। हफ्ते में सी.जी.एम. को रिपोर्ट करें और सी.जी.एम. की रिपोर्ट आए हमारे यहां दिल्ली को, तब हम उसको मानीटर करें और जिस अधिकारी के नीचे 3 महीने तक लगातार कोई सुधार न हो उसके लिए किसी दण्ड का प्रावधान किया जाए। इसीलिए हमने यह किया है।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, it is true that, as some of the Members made out, one of the basic objectives of the National Telecom

Policy in terms of inducing the private sector was to wipe out the waiting list so far as telephones are concerned, particularly so far as the village telephones are concerned. Now, what is revealed from the existing waiting list is that the lag in terms of availability of village telephones is not even; it is uneven and it is concentrated in certain telecom circles. The results of the bidding also show that for those circles for which there is no bidding, for which no private company is coming forward or also for those circles where the waiting lists of village telephones are the highest, the basic contention that was made out in arguing for the National Telecom Policy, in my opinion, was not vailed. Therefore there is need for further augmenting the allocation for wiping out the waiting lists of village telephones from the DoT funds itself, and as we know, as distinct from some other Government Departments, DoT is a revenue earning Department. But here also, Mr. Chairman Sir, the answer that we got last year, in 1995, was that the DoT's target had fallen short. Is it a fact that there was a delay on the part of the DoT to actually order supply of equipments in a systematic manner so that the kind of target and the kind of efficiency that the DoT was actually having could not be maintained? ....*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Please sum up and put your question.

SHRI NILOTPAL BASU: Is there any conscious Government attempt from within the DoT to sabotage its own programme?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: चेयरमैन सर, माननीय हमारे मित्र जी ने जो कहा है कुछ हद तक सही है। पिछले वक्त एक लाख पांच हजार का लक्ष्य था जिसमें 31,496 टेलीफोन ही लग पाए। इक्विपमेंट सप्लाई में देरी की वजह से ही ऐसा हुआ। जो इक्विपमेंट के सप्लाई के आर्डर्स दिए गए कुछ वे भी देर में दिए गए। लेकिन हमने इस वर्ष उसमें काफी परिवर्तन किया है। हमने सब बजटरी एलोकेशन भी अलग कर दिया है और श्रीमन् इस वर्ष जो जानकारी हमको दी गई है उसके अनुसार इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है। इस वर्ष शत-प्रतिशत लष्य को हम प्राप्त कर लेंगे और सुधार के लिए हमने पहले ही माननीय सदन के सामने निवेदन कर दिया कि हम इस पर स्वयं गंभीर हैं और कोशिश करेंगे कि ग्रामीण टेलीफोन सुविधा में सुधार हो।

श्री नीलोत्पल बसु: कोई प्रयास था कि सप्लायी में देर हो, आर्डर करने में क्या देर हुआ और कैसे देर हो गई?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: आर्डर में देरी हुई। कैसे हुई, यह पता नहीं, लेकिन आर्डर में देरी हुई।

श्री नीलोत्पल बसु: इसके बारे में कोई जांच आप करवायेंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और यह जिम्मेदारी लगाने की कोशिश करेंगे या नहीं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् इसको जरूर दखेंगे और अगर किसी की नीयत में कोई ऐसी बात हुई तो हम इसको देखेंगे, मगर वैसे ही कोई गड़बड़ होगी तो गलती नहीं है। लेकिन अगर गलत नीति से हो तो उसको हम अवश्य देखेंगे।

श्री नरेश यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1995-96 में बिहार में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सेवा को जोड़ने का लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: यह जब कहीं पर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो बिहार का भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और श्रीमन्, सब से ज्यादा अगर ग्रामीण टेलीफोन सुविधा की कमी है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ही है और इस वर्ष जो लक्ष्य रखा गया है वह इन तीन प्रांतों में, दूसरे अन्य प्रांतों के मुकाबले में ज्यादा है।

Plight of Indians in Gulf Countries

*202. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:
SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:†

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some Indian citizens are leading a very miserable life in various Gulf countries;

(b) whether Government have conducted any official level inquiry in this regard and the steps taken so far; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) The living conditions for Indian citizens in various gulf

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kanaksinh Mohansinh Mangrola.